

(च) क्या सभी राज्यों ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रतिखण्ड कम से कम 40 युवकों को प्रशिक्षित किया जाना है। तदनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग 10 लाख युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इसकी शुरुआत से लेकर 1983-84 तक प्रशिक्षित किए गए युवकों की संख्या 8.03 लाख है।

(ग) 1982-83 और 1983-84 में "ट्राइसेम" के अन्तर्गत शामिल किए गए आदिवासी और अनुसूचित जाति के युवकों की संख्या क्रमशः 25762 और 80969 है।

(घ) "ट्राइसेम" के अन्तर्गत 1983-84 तक प्रशिक्षित 8.03 लाख युवकों में से 4.38 लाख युवक अपना धन्धा/नौकरी करने लगे हैं।

(ङ) अपना धन्धा करने वाले युवकों की संख्या 3.90 लाख है।

(च) जी हां।

Unfair Dealings in Sales of Tractors

1197. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that representations have been received complaining against the unfair dealings in the sale of tractors to farmers;

(b) if so, the action taken on these representations ;

(c) whether it has been brought to the notice of his Ministry that the entire cost of tractor is got deposited from the farmers much in advance in clear violation and contravention of the instructions and orders issued under the Act of 1971; and

(d) if so, the action Government propose to take to put an end to such malpractice ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) :

(a) Yes, Sir.

(b) The matter has been taken up with the manufacturer concerned and with the Ministry of Industry which is responsible for manufacture and distribution of tractors.

(c) and (d) It has been reported that the entire cost of HMT 5911 model of tractor is being got deposited from the farmers in advance. However, since this model of tractor is not covered under the Tractors (Distribution and Sale) Control Order, 1971, which is administered by the Department of Heavy Industry, there is no contravention of any provision of the Order.

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धन का आबंटन

1168. श्री सत्यनारायण जाटया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बनान की कृपा करेंगे कि :